AFR

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

एफ०ए०एम० नंबर- **138/2012**

विजय कुमार गुप्ता आ० रामलाल गुप्ता, उम्र-**46** वर्ष,
साकिन- सती बाजार रायपुर, थाना- सिटी कोतवाली छ०ग०

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

श्रीमती किरण बाला, पति- विजय कुमार गुप्ता, उम्र- **41** वर्ष,
साकिन- इशा कॉम्पलेक्स, चुडी लाईन, गोलबाजार, रायपुर, छ०ग०
थाना- गोलबाजार रायपुर, छत्तीसगढ़

..... प्रतिवादिनी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एफ०ए० नंबर- **116/2003**

विजय कुमार गुप्ता आ० रामलाल गुप्ता, उम्र-**46** वर्ष,
साकिन- सती बाजार रायपुर, थाना- सिटी कोतवाली छ०ग०

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

श्रीमती किरण बाला, पति- विजय कुमार गुप्ता, उम्र- **41** वर्ष,
साकिन- इशा कॉम्पलेक्स, चुडी लाईन, गोलबाजार, रायपुर, छ०ग०
थाना- गोलबाजार रायपुर, छत्तीसगढ़

..... प्रतिवादिनी

.....

अपीलार्थी - पति	:	श्री मनय नाथ ठाकुर, अधिवक्ता वास्ते श्री बी०पी० शर्मा अधिवक्ता
प्रतिवादिनी - पत्नी	:	श्री राहुल मिश्रा, अधिवक्ता वास्ते श्री वाई०सी० शर्मा अधिवक्ता

29-11-2019

1. उपरोक्त दो अपीलों को इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है। अपीलकर्ता-पति ने प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ 2012 की एफ०ए०एम०संख्या 138 को प्रस्तुत किया है, जो 17.9.2012 के फैसले और डिक्री से दुखिद है जिसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) के तहत क्रूरता और त्याग करने के आधार पर तलाक के डिक्री के अनुदान के लिए अपीलकर्ता के आवेदन को बर्खास्त किया गया है ।

2. 2003 की पहली अपील संख्या 116 को अपीलकर्ता-पति द्वारा 6.5.2003 के निर्णय और आदेश से पीड़ित होकर प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा विद्वान कुटूम्ब न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अधीन पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के लिए आवेदन को स्वीकार किया है ।

3. अपीलकर्ता-पति ने प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ तलाक के आदेश के अनुदान के लिए एक आवेदन दाखिल किया, जो उस समय उनकी शादी दिनांक 21.02.1985 को हुई थी और अगस्त 1986 में एक बेटी रोशनी का जन्म उनके विवाह से हुआ था। अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता पर जोर दिया कि वह उसे अपने साथ बॉम्बे ले जाए जहां अपीलकर्ता एक नौकरी में लगा रहा था, हालांकि यह सूचित किया गया कि बॉम्बे में पति का कोई स्वतंत्र घर नहीं है और वह दूसरों के साथ भुगतान करने वाले अतिथि के रूप में साझा रह रहा है। प्रतिवादी-पत्नी ने बहुत जिद्दी दृष्टिकोण अपनाया और घोषणा की कि वह रायपुर में नहीं रहेगी और झगड़ा शुरू किया, जिससे परिवार में शांति भंग हो गई। पत्नी के जोर के कारण, आखिरकार, अपीलकर्ता को नवंबर 1985 में एक फ्लैट किराए पर लेकर अपनी पत्नी को बम्बे ले जाना पड़ा। प्रतिवादी-पत्नी बिल्कुल भी समझौता नहीं कर रही है और वह अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों के साथ रहने के लिए कभी तैयार नहीं थी। आगे कहा गया कि बॉम्बे में भी प्रतिवादी-पत्नी अपीलकर्ता को सूचित किए बिना घर को बंद करती थी और अक्सर बाहर जाती थी और अपीलकर्ता को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता था जब अपने घर लौटने पर वह घर को पत्नी द्वारा बंद पाता था। पत्नी शांति से नहीं रह रही थी। वह एक भटकारा की तरह यहाँ और वहाँ घूमने की आदी थी, उसकी कोई आत्मीयता नहीं थी, वह झगड़ा करती थी और घर के माहौल को तनावपूर्ण बनाती थी। जब अपीलकर्ता हैदराबाद और पुणे में तैनात रहता था, तब भी प्रतिवादी-पत्नी ने असामान्य व्यवहार किया। लौटने पर वह विवाहित घर में रहने के बजाय तुरंत अपने माता-पिता के घर जाती थी। प्रतिवादी-पत्नी अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों को वित्तीय मदद देने पर झगड़ा करती थी और आत्महत्या की धमकी भी देती थी। पत्नी की बहन की शादी के समय पत्नी की तरफ से भी काफी झगड़ा हुआ था। फरवरी 1989 में, प्रतिवादी-पत्नी ने झगड़ा करने के बाद अपना कुछ सामान उठाया और अपीलकर्ता के घर से निकल गई और बाद में, ससुर ने सूचित किया कि प्रतिवादी-पत्नी वैवाहिक घर नहीं लौटेगी क्योंकि उन्होंने सभी संबंध तोड़ दिए हैं। उन्होंने अपीलकर्ता से सभी समान भेजने को भी कहा जो प्रतिवादी का है, अन्यथा उचित

कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रतिवादी-पत्नी अपीलकर्ता को बताती थी कि उसकी शादी उसकी इच्छा के खिलाफ हुई है, वह राजनीति में सक्रिय रहना चाहती है और किसी भी दायित्व से मुक्त जीवन जीना चाहती है। वह ज्यादातर वैवाहिक दायित्वों की कीमत पर राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहती थी, नींद की गोलियों का सेवन करके आत्महत्या करने की धमकी देती थी। इसलिए, अपीलकर्ता को क्रूरता और त्याग करने के आधार पर तलाक का आदेश दिया जा सकता है क्योंकि दोनों पक्ष 16 वर्षों से अलग से रह रहे हैं। यह भी याचिका दी गई थी कि मामले की लंबित अवधि के दौरान भी, अपीलकर्ता-पति को क्रूरता का शिकार किया गया क्योंकि पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश के खिलाफ अपील की लंबित अवधि के दौरान, प्रतिवादी-पत्नी ने जबरन अपीलकर्ता के घर में प्रवेश किया जहां अपीलकर्ता का भाई अपनी बर्तन की दुकान चला रहा था और अटैचमेंट की कार्यवाही शुरू की गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आपराधिक कार्यवाही के परिणाम स्वरुप उसे जेल में रहना पड़ा। इसलिए अपीलकर्ता पर बहुत क्रूरता हुई।

4. प्रतिवादी-पत्नी ने उन सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने उसे क्रूरता का शिकार किया है। वह अपनी पत्नी को अपने साथ बॉम्बे में अपनी नौकरी के स्थान पर ले जाने को तैयार नहीं था और अपनी पत्नी को रखने की उपेक्षा कर रहा था। पति की मां और भाई ने उसे क्रूरता का शिकार किया और उसकी वैध मांग कि उसे अपने पति के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, परिवार के सदस्यों के लिए स्वीकार्य नहीं थी और उसे यह कहकर परेशान किया जा रहा था कि वह शादी के समय उचित उपहार नहीं लाई थी। कई मौकों पर, उसे अनैतिक रूप से विवाह के घर से बाहर निकाला गया था। पुना और हैदराबाद में भी अपनी पद के दौरान पति अपीलकर्ता पत्नी और शिशु के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में गंभीर नहीं था और उसे कई अवसरों पर पिटाई और डांटने का शिकार किया गया था। बच्चे को खिलाने के लिए उसे पड़ोसियों और दूसरों की दया पर रहना पड़ा। जब उसने जहरीले कीट से शिशु को काटने की घटना के बाद बिस्तर खरीदने की सलाह दी, तो अपीलकर्ता के पति ने दुर्व्यवहार किया। उसे दिन-प्रतिदिन की बैठक के लिए पर्याप्त पैसा नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कभी आत्महत्या की धमकी नहीं दी और न ही किसी मंच पर किसी भी क्रूर कार्य की कोई रिपोर्ट दर्ज की। अपनी बहन की शादी के समय अपीलकर्ता ने दुर्व्यवहार किया और प्रतिवादी-पत्नी को शादी में भाग लेने के लिए भेजने से इनकार कर दिया और बहुत बार कहने के बाद, वह सहमत हो गया लेकिन वह खुद शादी में भाग लेने नहीं गया। जब उसके पति ने बार-बार अनुरोधों के बावजूद उसे विवाह के घर में वापस नहीं लिया उसे अंततः पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा और उसके पक्ष में एक डिक्री पारित होने के बावजूद, अपीलकर्ता डिक्री को लागू करने से बच रहा था। वैवाहिक घर में निवास स्थान मांगने के उसके कृत्य को क्रूरता का कृत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके पास न केवल अपने पक्ष में पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास का डिक्री था, बल्कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के खिलाफ महिलाओं के संरक्षण के प्रावधानों के तहत, वह उसकी धारा 17 के तहत उपलब्ध निवास के अधिकारों के हकदार भी है।

5. पक्षों की उपर्युक्त याचिकाओं पर, पारिवारिक अदालत ने इस प्रश्न को निर्धारित

किया कि क्या अपीलकर्ता-प्रतिवादी क्रूरता और त्याग करने के आधार पर तलाक के आदेश का अधिकार है। पक्षों को मौखिक और दस्तावेजिक साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देने के बाद, विवादित फैसले और डिक्री के माध्यम से, विद्वान पारिवारिक अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता-पति क्रूरता और तोड़फोड़ के आरोप को साबित करने में विफल रहा और मुकदमा खारिज कर दिया।

6. प्रतिवादी-पत्नी ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्वास के अधिकार के अनुदान के लिए एक आवेदन दाखिल किया, अन्य बातों के अलावा, यह कहते हुए कि वर्ष 1985 में शादी के बाद और 1986 में बेटी के जन्म के बाद पत्नी अपने पति के साथ पुना और हैदराबाद में अपनी पोस्टिंग के विभिन्न स्थानों पर रहती थी। लेकिन बाद में जब उसके पति को बॉम्बे में तैनात किया गया और उसे मां और भाई के साथ छोड़ दिया गया, तो उसे डांटने और उत्पीड़न का शिकार किया गया। दिसंबर 1985 में बॉम्बे से रायपुर लौटने के बाद वे सास और बहनोई के साथ रहना शुरू कर दिए, उन्होंने पति को इस आरोप पर परेशान करने के लिए उकसाना शुरू किया कि शादी के समय उचित सामान उपहार नहीं दिए गए थे और पति उसे अनदेखा करता था और पति, सास और बहनोई द्वारा उसे मानसिक क्रूरता का शिकार किया गया था। जब वह गर्भावस्था में थी तो उससे मारपीट की गई और वैवाहिक घर में रहने की इच्छा के बावजूद वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया। हतोत्साहित करने और परेशान करने के सभी प्रयास किए गए थे ताकि वह वैवाहिक घर में न रहे। बलोदाबाजार में साल 1989 में बहन की शादी के बाद पति अपनी पत्नी को वापस लेने नहीं आया। मार्च 1992 में, हालांकि मध्यस्थता के बाद, पति ने पत्नी को वापस लेने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन आठ दिन बाद, उसे अपनी इच्छा के खिलाफ माता-पिता के घर वापस भेज दिया गया और तब से वह बेटी रोशनी के साथ बलोदा बाजार में रह रही है। पत्नी और उसके रिश्तेदारों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद पति ने कोई प्रयास नहीं किया कि पत्नी और बच्चे को वैवाहिक घर वापस लाने के लिए कदम उठाए जिसके कारण पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के लिए आवेदन दाखिल किया गया।

7. आरोपों से इनकार करते हुए पति ने कहा कि पत्नी पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के लिए जिम्मेदार है। उचित दहेज नहीं लाए जाने के आधार पर उत्पीड़न के आरोपों को अस्वीकार किया । तलाक के आदेश की मांग करने वाले पति द्वारा की गई क्रूरता का आरोप पत्नी के दावे का विरोध करने का आधार बनाया, इस दलील पर कि प्रतिवादी-पत्नी अनावश्यक रूप से जोर दे रही थी कि वह सभी कठिनाइयों के बावजूद अपने पति के साथ बॉम्बे में रहेगी और जब उसे रायपुर के वैवाहिक घर में वापस रहने के लिए कहा गया तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया और तनाव का माहौल पैदा किया। पत्नी हमेशा क्रूरता से काम करती थी, वह झगड़ा करती थी। पति के साथ अलग-अलग स्थानों पर रहने के दौरान जहां वह तैनात और काम कर रहा था, पत्नी ने हर छोटे मामले पर झगड़ा कर क्रूरता से काम किया। वह घर में ताला लगाती थी और बाहर जाती थी और जल्दी नहीं लौटती थी। मार्च 1992 में पत्नी अपने माता-पिता के घर गई और ऐसा नहीं है कि पति उसे बाहर निकाल देता था। पत्नी वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, क्रूरता से व्यवहार करने, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न होने के कारण, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्वास के लिए उसका आवेदन बिल्कुल भी सही नहीं है।

8. नीचे अदालत ने पक्षों को मौखिक और दस्तावेज़ सबूत देने की अनुमति देने के बाद एक निष्कर्ष दर्ज किया कि शादी के समय कम दहेज लाने के आरोप के संबंध में पत्नी के विरुद्ध क्रूरता की गई, उसे अपमानजनक टिप्पणियों के अधीन किया गया था और क्रूरता और पीटने के अधीन भी किया गया था।

9. पति के पक्ष में विद्वान वकील, 2012 की फैम संख्या 138 में पारित फैसले और डिक्री का तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने न केवल विवाहिक जीवन की लंबी अवधि में पत्नी द्वारा समय-समय पर उसके साथ क्रूरता का प्रकरण विशेष रूप से दायर की थी बल्कि पति द्वारा उसके साथ बमबे में रहने की अनावश्यक मांग करने में पति द्वारा किए गए क्रूरता के कई उदाहरणों को साबित करने के लिए विशिष्ट सबूत भी दिए थे । पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश के आधार पर निवास स्थल में रहने पर जोर देते हुए क्रूरता से कार्य करना, पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाना, जिससे कार्यवाही शुरू हो जाती है, शांति बनाए रखने और पति को जेल भेज दिया जाता है। वह आगे तर्क देंगे कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता के चरित्र की हत्या के लिए अपमानजनक समाचार फैलाकर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनता की नजर में अपीलकर्ता के सम्मान को कम करने में दुर्भावनापूर्ण कार्य किया। हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सबूतों में तुच्छ विरोधाभास को अनुचित भार देते हुए तलाक का डिक्री देने से इनकार कर दिया। अपीलकर्ता-पति के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि विद्वान निचली अपील अदालत ने तलाक के अनुदान के लिए आवेदन को खारिज करते हुए यह ध्यान में न रखते हुए अनदेखा किया कि पक्ष 1992 से अलग रह रहे हैं और इन लंबे वर्षों में उनके बीच विवाद की पृष्ठभूमि में, विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया और किसी भी पक्ष को एक साथ आने में रुचि नहीं थी। इसलिए 1992 से अलग रहने वाले पक्षों की इन अत्यंत साबित परिस्थितियों के सामने तलाक का आदेश दिया जाना चाहिए। अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली, (2006) 4 एससीसी 558, समर घोष बनाम जया घोष (2007) 4 एससीसी 511, विश्वनाथ अग्रवाल एस. ओ. सीताराम अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल (2012) 7 एससीसी 288 और के. श्रीनिवास राव बनाम डीए दीपा (2013) 5 एससीसी 226 डीए के मामलों में फैसलों पर निर्भर रखा।।

10. प्रतिवादी पत्नी के विद्वान वकील तर्क देंगे कि विद्वान परिवार अदालत ने सावधानीपूर्वक जांच और साक्ष्य की जांच के बाद पाया है कि अपीलकर्ता का मामला स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि मुख्य आरोप यह था कि पत्नी अपने पति के साथ रहने पर जोर दे रही थी, जहां भी वह नौकरी के संबंध में तैनात था, क्रूरता के कार्य के रूप में नहीं कहा जा सकता क्योंकि पत्नी ऐसी मांग बढ़ाने में काफी वैध है। अगली दलील यह है कि यह आरोप कि विवाहित घर में पत्नी की सास और भाई के साथ झगड़ा हुआ है एक गढ़ी हुई कहानी है क्योंकि अपीलकर्ता, उसकी पत्नी और भाई द्वारा कथित क्रूरता के संबंध में सबूतों में गंभीर विरोधाभास हैं। कथित क्रूरता के संबंध में इन सामग्री विरोधाभास पर ध्यान दिया गया और विद्वान पारिवारिक अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित रूप से सराहना की कि क्रूरता का आरोप नहीं लगाया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि पत्नी के खिलाफ यह आरोप कि उसने पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश की ताकत से विवाह के

घर में प्रवेश करने पर जोर दिया, किसी भी कल्पना से, यह एक कूररता पूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि पहली जगह पत्नी ने केवल निवास का स्थान पाने की मांग की थी क्योंकि उसके पक्ष में पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास का आदेश था। अन्यथा, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत, पत्नी हमेशा वैवाहिक घर में निवास का अधिकार रखती है। पत्नी ने न तो थाने में पति के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई और न ही कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज किया। पुलिस ने शांति व्यवस्था में अशांति के कारण कार्यवाही की और मजिस्ट्रेट ने उसके पति के खिलाफ शांति बनाए रखने की कार्यवाही की। प्रतिवादी-पत्नी ने कभी पति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया और पत्नी के अधिकारों की वापसी के लिए आवेदन दायर करने के अलावा, उसने कभी भी अपने पति के खिलाफ किसी मंच में कोई शिकायत दर्ज नहीं की क्योंकि वह हमेशा अपनी नाबालिग बेटी के वैवाहिक जीवन और भविष्य को बचाने के लिए तत्पर थी।

11. पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश के विरुद्ध, अपीलकर्ता-पति का मामला यह है कि पुनर्वास यांत्रिक तरीके से दिया गया है। वह यह कहेंगे कि तलाक याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को लगातार झगड़े में लिप्त होने और अनावश्यक मांग करके उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार किया था, इस बारे में विवरण दिया गया है, जिसे विशिष्ट निचली अदालत ने उचित रूप से सराहना नहीं की है। वह आगे प्रस्तुत करेगा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपनी इच्छा से मार्च 1992 महीने में विवाहित घर छोड़ दिया था और उसके बाद वह कभी विवाहित घर नहीं लौटी और उसके लंबे 16 साल बाद उसने विवाहित अधिकारों की पुनर्वास के लिए आवेदन दाखिल किया।

12. प्रतिवादी-पत्नी के विशिष्ट वकील का तर्क होगा कि विशिष्ट निचली अदालत ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सबूतों, विशेष रूप से क्रूरता के आरोपों की जांच के बाद स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि पत्नी क्रूरता का शिकार हुई थी और ऐसा नहीं है कि उसने पति को क्रूरता का शिकार किया था। विचारण अदालत ने यह भी दर्ज किया कि पत्नी ने वैवाहिक घर नहीं छोडा था, बल्कि उसे क्रूरता और जबरन और उसकी इच्छा के खिलाफ माता-पिता के घर वापस भेज दिया गया था और तब से पत्नी, उसके परिवार के सदस्यों और अन्य मध्यस्थों द्वारा बार-बार किए गए प्रयासों के बावजूद अपीलकर्ता बिना किसी आधार और उचित कारण के पत्नी और नाबालिग बच्चे के लिए निवास स्थान प्रदान करने से बच रहा था । इसलिए, पत्नी के अधिकारों के डिक्री का अनुदान अवैध नहीं है।

13. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है, दोनों मामलों में नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों को पढ़ा है, एक पति द्वारा दायर तलाक के आदेश की मांग करने वाली याचिका से संबंधित और पत्नी द्वारा दायर पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के लिए आवेदन से संबंधित अन्य, जिनमें से उपरोक्त दो अपील उठी हैं।

14. अपीलकर्ता पति विजय कुमार गुप्ता ने क्रूरता और त्याग करने के दोहरे आधार पर

तलाक का आदेश मांगा। पारिवारिक अदालत ने कोई भी आधार साबित नहीं पाया और आवेदन खारिज कर दिया। हम पहले इस बात पर विचार करेंगे कि क्या विद्वान परिवार अदालत के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार है कि अपीलकर्ता-पति प्रतिवादी-पत्नी द्वारा त्याग करने को साबित करने में विफल रहा है। विनम्र परिवार अदालत ने अपने फैसले के पैरा-43 से 47 में मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के मूल्यांकन पर विस्तृत विचार किया है। पति विजय का सबूत है कि फरवरी 1989 में प्रतिवादी-पत्नी अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए बलोदा बाजार गई थी और उस समय उसके पिता और अन्य रिश्तेदार उसे अपने साथ ले जाने आए थे और उस समय, वे झगड़ा कर पत्नी से यह कहकर अपना सारा सामान रखने को कह रहे थे कि वह फिर नहीं लौटेगी और इस प्रकार प्रतिवादी-पत्नी ने विवाहित घर छोड़ दिया और अपीलकर्ता को छोड़ दिया और कभी नहीं लौटी, प्रतिवादी-पत्नी किरणबाला के सबूतों को देखते हुए अविश्वास किया गया कि जब उसके पिता पति और परिवार के सदस्यों को शादी में भाग लेने के लिए आए थे, तो पति, सास, बहनोई ने दुर्व्यवहार किया और साथ ही साथ मारपीट की। नीचे विद्वान अदालत ने प्रतिवादी-पत्नी के सबूतों पर विचार किया था कि वह वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए 1992 में वैवाहिक घर लौट आई और वहां रह गई, लेकिन फिर से उनका अपमान किया गया और अनैतिकता से बाहर निकाल दिया गया। उसका सबूत यह है कि पति ने विवाह के अधिकारों की वापसी की मांग के लिए अदालत का रुख किया और विवाह के अधिकारों की वापसी के आदेश के खिलाफ, कोई रोक नहीं होने के बावजूद, पति उसे वापस पति के घर ले जाने से बच रहा है और तलाक के लिए मुकदमा दायर कर रहा है, भी विचार किया गया है। नीचे विद्वान अदालत ने यह विचार किया है कि,प्रतिवादी-पत्नी ने वैवाहिक संबंध फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है और उसका तलाक देने का कोई इरादा नहीं था। नीचे विद्वान अदालत ने यह भी विचार किया है कि मध्यस्थता और पुनर्मिलन की सभी कार्यवाही के परिणाम स्वरुप प्रतिवादी-पत्नी अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए तैयार है, अपीलकर्ता ने फिर से एकजुट होने से इनकार कर दिया। पत्नी की फरवरी 1989 में अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए विवाह के घर छोड़कर और पूरे सामान भेजने की आवश्यकता के वादी का साक्ष्य विश्वसनीय सबूतों की कमी के कारण स्वीकार नहीं किया गया है। नीचे दिए गए अदालत ने अपीलकर्ता की मां के विरोधाभासी सबूतों पर भी विचार किया है। सावित्री गुप्ता (AW4) ने कहा कि 1989 में किरणबाला (प्रतिवादी-पत्नी) कभी घर नहीं आई थी और इसलिए उसने अपना सामान और मार्कशीट नहीं लिया था और इस प्रकार अपीलकर्ता-पति के सबूतों का समर्थन नहीं करते हुए भी विचार किया गया है।

15. शिकायत में, उसके पैराग्राफ 9, 10, 12 और 19 में त्याग करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के आरोप के अनुसार प्रतिवादी-पत्नी अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए घर छोड़कर बलोदा बाजार गई। उस समय पिता आए थे, झगड़ा हुआ और प्रतिवादी-पत्नी से अपना सामान लेने और भविष्य में नहीं लौटने के लिए कहा। प्रतिवादी पत्नी का पिता रायपुर आते थे और अपीलकर्ता पति को सूचित करते थे कि उसकी बेटी वापस नहीं आएगी और उसकी बेटी का जो भी सामान वैवाहिक घर में पड़ा है, उसे वापस भेजा जा सकता है। इसलिए, अपीलकर्ता-पति के अनुसार, प्रतिवादी-पत्नी ने उसे वर्ष 1989 में छोड़ दिया और वापस नहीं आई। हालांकि, प्रतिवादी-पत्नी ने अपने साक्ष्य में यह साबित कर दिया है कि पति उसे वापस लेने

कभी नहीं आया, इसलिए, वह मार्च 1992 में विवाहित घर में रहने गई थी, लेकिन कुछ समय बाद, उसे अपमान किया गया और फिर से अनैतिकता से विवाहित घर से बाहर निकाल दिया गया। प्रतिवादी के नेतृत्व में इस विशेष सबूत पर विवाद नहीं किया गया है। अपीलकर्ता विजय ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी की बहन की शादी में भाग लेने के लिए माता-पिता के घर जाने पर आपत्ति की थी, लेकिन वह यह नहीं बता सके कि उन्होंने अपनी पत्नी की अपनी बहन की शादी में भाग लेने पर आपत्ति क्यों की। इसके अलावा उन्होंने स्वीकार किया कि वह खुद शादी में शामिल होने नहीं गए। उसने क्रॉस-परीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी और बेटी को वापस वैवाहिक घर लाने का कोई प्रयास नहीं किया। फरवरी 1989 में पत्नी के माता-पिता के घर जाने का अवसर बिना किसी कारण के नहीं था बल्कि अपनी बहन की शादी के अवसर पर और यह बहुत स्वाभाविक है कि एक बहन हमेशा अपनी बहन की शादी में शामिल होना चाहती है। इसलिए, फरवरी 1989 में प्रतिवादी-पत्नी का विवाह से प्रस्थान केवल उसकी बहन की विवाह में भाग लेने के लिए था।

16. अपीलकर्ता के नेतृत्व में सबूत-पति कि प्रतिवादी के पिता-पत्नी और अन्य रिश्तेदार जो उसे शादी में भाग लेने आए थे, झगड़ा कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे और प्रतिवादी-पत्नी से उसका सामान लेने और वापस न आने को कहे थे, अन्य गवाहों के सबूतों से समर्थन नहीं किया गया है। अपीलकर्ता की मां सावित्री गुप्ता (AW4) खुद कहती है कि प्रतिवादी-पत्नी फरवरी 1989 में घर नहीं आई थी और इसलिए उसके लिए अपना सामान और मार्कशीट लेने का कोई अवसर नहीं था। अपीलकर्ता और प्रतिवादी के सबूत से एक बात स्पष्ट है कि जब प्रतिवादी-पत्नी अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए अपने माता-पिता के घर जाना चाहती थी, तो अपीलकर्ता-पति ने आपत्ति जताई थी, इसलिए प्रतिवादी के पिता और अन्य रिश्तेदार उसे माता-पिता के घर ले जाने आए थे और उस घटना में झगड़ा भी हुआ। अपीलकर्ता शादी में शामिल होने नहीं गया। सब कुछ इससे केवल यह अनुमान लगता है कि पति की आपत्ति के बावजूद, प्रतिवादी-पत्नी अपनी बहन की शादी में भाग लेने पर विवाद हुआ था, वह अपने माता-पिता के घर गई थी। लेकिन यह अपने आप में यह अनुमान नहीं लगाएगा कि वह अपने पति और सभी वैवाहिक दायित्वों को छोड़ने के इरादे से माता-पिता के घर गई थी। तोड़फोड़ के मामले में, जो महत्वपूर्ण है वह पक्षों का इरादा है। सिर्फ इसलिए कि पत्नी अपने पति के साथ झगड़े के पृष्ठभूमि में अपने माता-पिता के घर गई थी, कि अपने आप में, बिना कुछ और, पत्नी की ओर से अपने पति को छोड़ने का कोई इरादा साबित नहीं करता है।

17. इस मामले में, यह ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी-पत्नी ने विशिष्ट सबूत दिए थे कि जब उसका पति उसे और बच्चे को वापस वैवाहिक घर ले जाने नहीं गया था, तो अंत में वह मार्च 1992 में अपने वैवाहिक घर गई थी। पत्नी के इस सबूत पर निचली अदालत ने भरोसा किया है क्योंकि यह निर्विवाद रहा है। दूसरी ओर अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने कभी भी अपनी पत्नी को वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही उसकी पत्नी के घर गया है। इस प्रकार, वैवाहिक दायित्व को फिर से शुरू करने की दिशा में कदम उठाने के लिए अपीलकर्ता की ओर से पूरी तरह से सबूत नहीं होने के विपरीत, प्रतिवादी-पत्नी ने विशिष्ट सबूत दिए हैं कि

उसने वैवाहिक घर में वापस आने का प्रयास किया है और यह सौंप दिया है कि उसे फिर से अपमानित किया गया और बाहर फेंक दिया गया था।

18. पति के साक्ष्य की तुलना में, संभावनाओं के पैमाने पर अधिक भार पत्नी के साक्ष्य में है क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन आवेदन दाखिल करके पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के लिए अदालत में दाखिल किया था। उन कार्यवाही में भी पति ने यह नहीं कहा पत्नी को वापस लेने की इच्छा रखते हैं। उत्तरदाता-पत्नी लगातार विवाह के घर लौटने की इच्छा व्यक्त करती रही और अंततः उसके पक्ष में डिक्री भी पारित की गई।

19. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-पति ने सबूत दिए हैं कि पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश पारित होने के बाद, प्रतिवादी-पत्नी ने खुद को वैवाहिक घर में धकेलने का प्रयास किया। वास्तव में, इस घटना और पत्नी के आचरण को अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता के आरोप को साबित करने के लिए सबूतों में नेतृत्व किया गया है। लेकिन फिर, जहां तक परित्याग के पहलू का सवाल है, पति-अपीलकर्ता द्वारा स्वयं अगुवाई किए गए यह सबूत, प्रतिवादी-पत्नी द्वारा परित्याग के अपीलकर्ता के मामले को ध्वस्त करता है। यदि किसी भी प्रकार के प्रतिवादी-पत्नी का अपने पति को छोड़ने का इरादा था, तो उसके लिए पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के लिए आवेदन करने, मामले पर विवाद करने, एक डिक्री प्राप्त करने और फिर पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के डिक्री के आधार पर विवाह के घर में प्रवेश करने का प्रयास करने का कोई कारण नहीं था। पत्नी का यह विशेष साबित आचरण, जिसपर ऊपर चर्चा की गई है, प्रत्यक्षवादी-पत्नी की ओर से अपीलकर्ता को छोड़ने के किसी भी इरादे को खारिज करता है। इसके विपरीत, यह साक्ष्य अधिक संकेत देते हैं कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है क्योंकि वह फरवरी 1989 में अपनी बहन की शादी में भाग लेने गई थी जो अपीलकर्ता के लिए स्वीकार्य नहीं थी और जिसके कारण कुछ विवाद भी हुआ था।

20. उपरोक्त विचार के मद्देनजर, इस अदालत को विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दर्ज इस निष्कर्ष को उल्लटने का कोई प्रर्याप्त आधार नहीं मिला कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी-पत्नी ने उसे छोड़ दिया है, ताकि तलाक के आदेश के अनुदान का आधार बन सके।

21. अब हम अभिलेखित याचिकाओं और सबूतों के प्रकाश में निचली अदालत की निष्कर्षों की जांच करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या निम्न अदालत ने यह मानकर गलत किया है कि अपीलकर्ता-पति क्रूरता साबित करने में विफल रहे। हमने यहां उल्लेख किया है कि शिकायत में अपीलकर्ता पति द्वारा कई छोटी घटनाओं की याचिका की गई है, जिसमें पति के साथ बॉम्बे में रहने के लिए प्रतिवादी का जोर, सास और भाई के साथ रहने के लिए उसकी अनिच्छा, झगड़ा व्यवहार और अक्सर माता-पिता के घर जाने की प्रवृत्ति और कभी-कभी पति के पद के स्थान से लौटने के बाद माता-पिता के घर जाना शामिल है। उपरोक्त के अलावा, अपीलकर्ता ने कड़े प्रमाण प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा गया कि पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश के खिलाफ अपील के लंबित होने के दौरान प्रतिवादी-पत्नी ने जबरन विवाह के घर में प्रवेश करने का प्रयास किया जिससे शांति में अशांति पैदा हुई और पुलिस पहुंची और

तब एक अप्रिय स्थिति पैदा हुई जब पति को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, धारा 107, 110 के तहत कार्यवाही की। कार्यवाही को इतना खींचा गया कि उसे जेल में भी रहना पड़ा। इस विशेष घटना और पत्नी के आचरण को अपीलकर्ता-पति द्वारा क्रूरता का मामला बनाने का मुख्य आधार बनाया गया है, यह प्रस्तुत करके कि इस आचरण के द्वारा प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता और परिवार के सभी सदस्यों को परेशान किया और इस प्रकार क्रूरता की कदम उठाई। हालांकि क्रूरता के पहलू पर रिकॉर्ड में दलीलों और सबूतों का मूल्यांकन करने से पहले, हम नवीन कोहली (उपरोक्त) के मामले में क्रूरता का क्या गठन है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रसिद्ध फैसले का उल्लेख करना उपयुक्त समझते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अंग्रेजी और भारतीय कानून दोनों में क्रूरता की अवधारणा की जांच की, ताकि यह आकलन किया जा सके कि हाथ में मामले में क्रूरता का मामला बनाया गया है या नहीं। क्रूरता जैसा कि पाठ और न्यायिक घोषणा में समझा जाता है, को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः

[1]"38..." क्रूरता जो विवाह के विघटन का कारण है, उसे ऐसे स्वेच्छयापूर्ण और अनुचित आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक रूप से खतरे का कारण बनता है या ऐसे खतरे की उचित आशंका पैदा करता है। "

[2]"39" क्रूरता की पुर्नरावृत्ति दिखाने के लिए बहुत मामूली ताजा सबूत की आवश्यकता है, क्योंकि चरित्र की क्रूरता आचरण और व्यवहार में खुद को दिखाने के लिए बाध्य है, प्रतिदिन एवं प्रतिरात ।

[3]40... "यह सच है कि मूल अपराध जितना गंभीर होगा, पुनरुद्धार के लिए बाद के कृत्यों की उतनी ही कम गंभीर आवश्यकता होगी।"

[4]41.... "यदि क्रूरता का दरवाजा बहुत चौड़ा खोला जाता है, तो हमें जल्द ही स्वभाव की असंगतता के लिए तलाक देना चाहिए. इस रास्ते पर चलना आसान है, खासकर एक पक्षीय मामलों में । ऐसे प्रलोभन का विरोध किया जाना चाहिए, ऐसा न हो कि हम ऐसी स्थिति में फिसल जाते हैं जहां विवाह की संस्था खुद खतरे में है।"

x x x x

x x x x

[5]44..... क्रूरता की व्यापक परिभाषा देना असंभव है, लेकिन जब निंदनीय आचरण या पति-पत्नी की दया के सामान्य मानकों से हटने से स्वास्थ्य को चोट पहुंचाई या उसकी आशंका होती है, तो मेरा मानना है कि यह क्रूरता है यदि एक उचित व्यक्ति

1 डी. टोलस्टॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "तलाक और विवाह के कारणों का कानून और व्यवहार" (छठा संस्करण, पृष्ठ 61) में लिखा
2 बर्ट्रैम बनाम बर्ट्रैम [(1944) पी 59] per Scott, L.J.
3 कूपर बनाम कूपर [(1950) 200 (एचएल)
4 लॉर्ड डेनिंग, एल.ज। Kaslefsky v Kaslefsky [(1950) 2 All ER 398, 403]:
5 लॉर्ड पीर्स ने देखा:

स्वभाव और अन्य सभी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद यह मानता है कि शिकायत की गई आचरण ऐसी है कि इस जीवनसाथी को इसे सहन करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

[6]45..."किसी ने कभी भी क्रूरता की व्यापक परिभाषा देने का प्रयास नहीं किया है और मैं ऐसा करने का प्रयास नहीं करना चाहता. बहुत कुछ प्रतिवादी के ज्ञान और इरादे पर निर्भर करना चाहिए, उसके (या उसके) आचरण की प्रकृति पर, और पति/पत्नी के चरित्र और शारीरिक या मानसिक कमजोरियों पर, और संभवतः कोई सामान्य बयान सभी मामलों में समान रूप से लागू नहीं है सिवाय इस आवश्यकता को छोड़कर कि राहत मांगने वाले पक्ष को जीवन, अंग या स्वास्थ्य को वास्तविक या संभावित चोट दिखानी चाहिए।"

22. सर्वोच्च न्यायालय ने 1964 से अपने निर्णयों की श्रृंखला द्वारा पैरा-46 से पैरा-65 (नवीन कोहिली का मामला)में बड़ी संख्या में निर्णयों की जांच पर विधि के सिद्धांतों को भी सारांशित किया । वह उपरोक्त निर्णय में उल्लिखित विभिन्न निर्णयों में की5. लॉर्ड पीर्स ने देखा: गई टिप्पणियों को निम्नलिखित रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः

"(क) कानूनी क्रूरता की अवधारणा सामाजिक अवधारणा और जीवन स्तर के परिवर्तन और उन्नति के अनुसार बदलती है. हमारी सामाजिक अवधारणाओं की उन्नति के साथ, इस विशेषता को विधायी मान्यता प्राप्त हुई है. कानूनी क्रूरता स्थापित करने के लिए, शारीरिक हिंसा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

हिंदू विवाह अधिनियम में क्रूरता शब्द की परिभाषा नहीं की गई है। यह अधिनियम की धारा 13 (1) (i) में मानव आचरण या वैवाहिक कर्तव्यों या दायित्वों से संबंधित या उसके संबंध में व्यवहार के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। यह एक व्यक्ति का आचरण है जो दूसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। यदि यह भौतिक है, तो यह तथ्य और डिग्री का सवाल है। यदि यह मानसिक है, तो क्रूर व्यवहार की प्रकृति और फिर इस तरह के व्यवहार के पति या पत्नी के मन पर प्रभाव के बारे में जांच शुरू होनी चाहिए। क्या इससे उचित आशंका पैदा हुई कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या हानिकारक होगा, अंततः आचरण की प्रकृति और शिकायतकर्ता पति या पत्नी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखकर निकाला जाना चाहिए। हालांकि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां शिकायत की गई आचरण पर्याप्त बुरी और स्वयं गैरकानूनी या अवैध है। तब दूसरे पति या पत्नी पर असर या नुकसानदायक प्रभाव की जांच या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, यदि आचरण स्वयं साबित या स्वीकार किया जाता है, तो क्रूरता स्थापित हो जाएगी। इरादे की अनुपस्थिति से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यदि मानव मामलों में साधारण अर्थ से, शिकायत की गई कृत्य को अन्यथा क्रूरता के रूप में माना जा सकता है। इरादा क्रूरता में आवश्यक तत्व नहीं है। पार्टी को राहत को इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वेच्छयापूर्ण या जानबूझकर दुर्व्यवहार नहीं हुआ है।

---

6 गोलिन्स बनाम गोलिन्स में लॉर्ड रीड [1964 AC 644: (1963) 2 सभी एर 966]:

C. क्रूरता का आरोप काफी हद तक जीवन के प्रकार पर निर्भर कर सकता है दोनों पक्ष अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों और उनके संस्कृति और मानवीय मूल्यों के आदी हैं जिन्हें वे महत्व देते हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय अपनी गुणवत्ता पर ही होनी चाहिए।

D. वे गृह विशेष या व्यक्ति विशेष में अलग-अलग डिग्री के होते हैं। जब जीवन या रिश्तों में साथी द्वारा क्रूरता के व्यवहार के बारे में कोई पति या पत्नी शिकायत करता है, तो अदालत को जीवन में मानक की तलाश नहीं करनी चाहिए। एक मामले में क्रूरता के रूप में व्यक्त किए गए तथ्यों का एक सेट दूसरे मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे और पार्टियों के बीच पीढ़ी का अंतर हो सकता है। बेहतर होगा अगर हम अपने रीति-रिवाजों और आचरण को एक तरफ रखें और मिसालों पर कम निर्भर करें क्योंकि उन्हें ऐसे मनुष्यों के आचरण से निपटना है जो आम तौर पर समान नहीं हैं। किसी भी प्रकार की क्रूरता में नया प्रकार हो सकता है मामला मानव व्यवहार, क्षमता या शिकायत किए गए आचरण को सहन करने की अक्षमता पर निर्भर करता है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i) में मानसिक क्रूरता को व्यापक रूप से उस आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूसरे पक्ष पर ऐसी मानसिक पीड़ा देता है, जिससे उस पक्ष के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना संभव नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि दोनों पक्षों से यथोचित रूप से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आहत पक्ष को यथोचित रूप से इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए नहीं कहा जा सके और यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि मानसिक क्रूरता ऐसी है जिससे याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते समय, पक्षों की सामाजिक स्थिति, शिक्षा स्तर, जिस समाज में वे चलते हैं, पक्षों की कभी एक साथ रहने की संभावना या अन्यथा, यदि वे पहले से ही अलग रह रहे हैं, तथा अन्य सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए जिन्हें विस्तृत रूप से निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। एक मामले में क्रूरता क्या है दूसरे मामले में क्रूरता के बराबर नहीं हो सकती है। यह तय करने के लिए प्रत्येक मामले को उस मामले की तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये। यदि यह आरोपों का मामला है, तो उस संदर्भ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें वे लगाए गए थे।

(f) "क्रूरता" शब्द को विवाहित मामलों में शब्द के सामान्य अर्थ में समझा जाना चाहिए। यदि शिकायत किए गए आचरण या क्रूर कृत्य की प्रकृति से नुकसान, परेशान या चोट पहुंचाने का इरादा अनुमान लगाया जा सकता है, तो क्रूरता आसानी से स्थापित 8 की जा सकती है। लेकिन इरादा की अनुपस्थिति से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी पक्ष के अनजाने पर लेकिन अक्षम्य आचरण से क्रूरता के उदाहरण हो सकते हैं। क्रूर व्यवहार पक्षों के बीच सांस्कृतिक संघर्ष के कारण भी हो सकता है। मानसिक क्रूरता किसी पक्ष के कारण हो सकती है जब दूसरे पति या पत्नी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता एक मानसिक रोगी है, या उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता है, कि

वह विकार और मतिभ्रम से पीड़ित है, और इसके अतिरिक्त, आरोप लगाने के लिए कि वह और उसके परिवार के सभी सदस्य पागलों का एक समूह हैं। याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य पागल हैं और यह आरोप कि उसके पूरे परिवार में पागलपन की एक लंबाई चलती है, यह भी मानसिक क्रूरता का कार्य है। मानसिक क्रूरता पति या पत्नी का वह आचरण है जो दूसरे के वैवाहिक जीवन में मानसिक पीड़ा या भय का कारण बनता है। इसलिए, "क्रूरता" याचिकाकर्ता के साथ ऐसी क्रूरता के साथ व्यवहार करने का अनुमान लगाती है कि दूसरे पति या पत्नी के मन में उचित आशंका पैदा करती है कि दूसरे पक्ष के साथ रहना उसके लिए हानिकारक होगा। हालांकि क्रूरता को पारिवारिक जीवन के साधारण पहलू से अलग करना होगा। यह निर्णय पीड़ित पति या पत्नी की संवेदनशीलता के आधार पर नहीं किया जा सकता और आचरण के पाठ्यक्रम के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए जो सामान्य तौर पर पति या पति के लिए दूसरे के साथ रहना खतरनाक होगा। क्रूरता की अवधारणा और इसका प्रभाव व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है जो उस व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है जिससे ऐसा व्यक्ति संबंध रखता है। उपरोक्त धारा के अधीन अपराध बनाने के उद्देश्यों के लिए 'क्रूरता' शारीरिक होने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि मानसिक यातना या असामान्य व्यवहार किसी विशेष मामले में क्रूरता और उत्पीड़न के बराबर हो सकता है।

(I) विवाह के मामले नाजुक मानवीय और भावनात्मक संबंधों के मामले हैं। यह आपसी विश्वास, सम्मान, प्यार और स्नेह की मांग करता है, जिससे जीवनसाथी के साथ उचित समायोजन के लिए पर्याप्त स्थान हो। रिश्ते को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भी होना चाहिए। ऐसे मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आते हुए वैवाहिक आचरण अब विनियम द्वारा नियंत्रित हो गया है। व्यक्तियों के हित में और व्यापक परिप्रेक्ष्य में, एक अच्छी तरह से बुना हुआ, स्वस्थ और अशांत और झरझरा समाज बनाने के लिए वैवाहिक मानदंडों को विनियमित करने के लिए इसे नियंत्रित करने की मांग की जाती है। विवाह की संस्था सामान्य तौर पर समाज में महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका निभाती है। इसलिए तलाक की राहत के लिए एक कठोर सूत्र के रूप में 'अपरिवर्तनीय रूप से टूटे हुए विवाह' की किसी भी प्रस्तुति को लागू करना उपयुक्त नहीं होगा। इस पहलू को मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए। इस अधिनियम में क्रूरता की अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है। क्रूरता जो विवाह के विघटन का कारण है, को ऐसे चरित्र के जानबूझकर और अनुचित आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक रूप से खतरे पैदा कर सकता है या ऐसे खतरे की उचित आशंका पैदा कर सकता है। मानसिक क्रूरता के प्रश्न को उस विशेष समाज के वैवाहिक संबंधों के मानदंडों, उनके सामाजिक मूल्यों, स्थिति, परिवेश के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए जिसमें वे रहते हैं। क्रूरता, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, में मानसिक क्रूरता शामिल है, जो विवाह की गलती के दायरे में आती है। क्रूरता की जरूरत शारीरिक नहीं होते। यदि उसके पति या पत्नी के आचरण से वही स्थापित हो जाए और/या वैध रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पति या पत्नी के साथ व्यवहार ऐसे है कि इससे दूसरे पति या पत्नी के मन में उसके मानसिक व्यवहार के बारे में आशंका पैदा हो जाती है कल्याण तो यह आचरण क्रूरता के बराबर है। मानव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यवहार या मानव व्यवहार के संबंध में 'क्रूरता' अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया गया है। यह वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित या उसके संबंध में आचरण है। क्रूरता एक का एक पाठ्यक्रम या आचरण है, जो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। अगर यह शारीरिक है तो अदालत को इसका निर्धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह तथ्य और डिग्री का सवाल है। यदि यह मानसिक है, तो समस्या कठिनाइयों को जन्म देती है। पहला, क्रूर व्यवहार की प्रकृति के बारे में जांच शुरू होनी चाहिए, दूसरा इस तरह के व्यवहार के पति या पत्नी के मन में प्रभाव, क्या इससे उचित आशंका पैदा हुई कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या हानिकारक होगा। अंततः, यह एक अनुमान का विषय है जो द्वारा खींचा जाना चाहिए आचरण की प्रकृति और शिकायत करने वाले पति या पत्नी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखना। हालांकि, ऐसा मामला हो सकता है जहां शिकायत की गई आचरण पर्याप्त बुरी और अपने आप में अवैध या अवैध है। तब दूसरे पति या पत्नी पर प्रभाव या नुकसान के प्रभाव की जांच या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, यदि आचरण स्वयं साबित या स्वीकार किया जाता है, तो क्रूरता स्थापित हो जाएगी।

(J) क्रूरता का गठन करने के लिए, शिकायत की गई आचरण "गंभीर और भारी" होनी चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता पति या पत्नी से दूसरे पति या पत्नी के साथ रहने की यथोचित उम्मीद नहीं की जा सकती। यह "वैवाहिक जीवन के साधारण पहनने और आंसू" से अधिक गंभीर होना चाहिए। परिस्थितियों और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आचरण का निष्कर्ष निकालने के लिए जांच की जानी चाहिए कि क्या शिकायत की गई आचरण विवाह कानून में क्रूरता के बराबर है। आचरण पर विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कई कारकों जैसे कि पार्टियों की सामाजिक स्थिति,उनकी शिक्षा, शारीरिक और मानसिक स्थिति, रीति-रिवाजों और परंपराओं एक सटीक परिभाषा निर्धारित करना या परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन करना मुश्किल है, जो क्रूरता का गठन करेगा। यह अदालत के विवेक को संतुष्ट करने के प्रकार का होना चाहिए कि दूसरे पति या पत्नी के आचरण के कारण पक्षों के बीच संबंध इतने बिगड़ गए हैं कि उनके लिए मानसिक पीड़ा, यातना या संकट के बिना एक साथ रहना असंभव होगा, शिकायतकर्ता को तलाक सुरक्षित करने का अधिकार देना होगा। शारीरिक हिंसा क्रूरता का गठन करने के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है और अमूल्य मानसिक पीड़ा और यातना को बढ़ाने वाला आचरण का एक सुसंगत पाठ्यक्रम अधिनियम की धारा 10 के अर्थ में क्रूरता का गठन कर सकता है। मानसिक क्रूरता में गंदा और अपमानजनक भाषा का उपयोग करके मौखिक अपमानजनक और अपमानजनक रूप से शामिल हो सकती है, जिससे दूसरे पक्ष की मानसिक शांति में लगातार अशांति होती है।

(K) क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका पर विचार करने वाली अदालत को यह ध्यान में रखना होगा कि उसके सामने समस्याएं मानव की हैं और तलाक की याचिका का निपटान करने से पहले पति या पत्नी के आचरण में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को ध्यान में रखना होगा। हालांकि, यह आचरण, अत्यंत मामूली या तुच्छ, किसी अन्य के मन में दर्द पैदा कर सकता है। लेकिन आचरण को क्रूरता कहने के पूर्व गंभीरता की एक निश्चित पिच को छूना चाहिए। यह अदालत के लिए है कि वह गुरुत्व का वजन

करे। यह देखना होगा कि क्या यह आचरण ऐसा था कि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता को सामान्य मानव जीवन के हिस्से के रूप में सहन करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। हर वैवाहिक आचरण, जो दूसरे को परेशान कर सकता है, क्रूरता के बराबर नहीं हो सकता है। साथ-साथ मामूली परेशानियां, पति/पत्नी के बीच झगड़े, जो दैनिक वैवाहिक जीवन में होता है, क्रूरता के बराबर नहीं हो सकती है। वैवाहिक जीवन में क्रूरता निराधार विविधता हो सकती है, जो सूक्ष्म या क्रूर हो सकती है। यह शब्द, इशारे या सिर्फ चुप्पी, हिंसक या अहिंसक हो सकता है। एक ध्वनि विवाह की नींव सहिष्णुता, समायोजन और एक दूसरे का सम्मान है। एक निश्चित सहनीय सीमा तक एक-दूसरे की गलती के प्रति सहिष्णुता हर विवाह में निहित होनी चाहिए। छोटे कथाओं, छोटे मतभेदों को अतिरंजित और बढ़ाया नहीं जाना चाहिए ताकि स्वर्ग में जो कहा जाता है वह बना हुआ है उसे नष्ट कर दिया जा सके। सभी झगड़ों को इस दृष्टिकोण से तौलना चाहिए कि प्रत्येक विशेष मामले में क्रूरता क्या है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमेशा पक्षों की शारीरिक और मानसिक स्थिति, उनके चरित्र और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जाना चाहिए। बहुत तकनीकी और अतिसंवेदनशील दृष्टिकोण विवाह की संस्था के लिए प्रतिप्रभावी होगा। अदालतों को आदर्श पति और आदर्श पत्नियों से निपटने की जरूरत नहीं है। इससे पहले किसी विशेष पुरुष और महिला से निपटना होगा। आदर्श जोड़े या सिर्फ आदर्श जोड़े के पास शायद विवाह अदालत में जाने का कोई अवसर नहीं होगा।

High Court of Chhattisgarh

23. समर घोष (उपरोक्त) के मामले में क्रूरता के संबंध में विधि की एक आधिकारिक घोषणा में पैरा-101 के निष्कर्ष में यह दोहराते हुए कि मार्गदर्शन के लिए कभी भी कोई समान मानक नहीं निर्धारित किया जा सकता है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने मानव व्यवहार के कुछ उदाहरणों को सूचीबद्ध करना उचित समझा जो मानसिक क्रूरता के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकते हैं। उन उदाहरणों का अर्थ विस्तृत नहीं बल्कि केवल चित्रण
है, जैसा कि उपरोक्त निर्णय में देखा गया है,निम्नलिखित हैंः "101.x x x x x x

(i) पक्षों के पूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर तीव्र मानसिक दर्द, पीड़ा और पीड़ा, जो पक्षों को एक-दूसरे के साथ रहना संभव नहीं बनाती है, मानसिक क्रूरता के व्यापक मापदंडों के भीतर आ सकती है।

(ii) पक्षों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन का व्यापक मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति है कि आहत पक्ष को यथोचित रूप से ऐसे आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ जीने के लिए नहीं कहा जा सकता।

(iii) केवल ठंडा व्यवहार या स्नेह की कमी क्रूरता के बराबर नहीं हो सकती, भाषा की अक्सर अशिष्टता, व्यवहार की अशिष्टता, उदासीनता और उपेक्षा इस स्तर तक पहुंच सकती है कि यह दूसरे पति या पत्नी के लिए वैवाहिक जीवन को बिल्कुल असहनीय बना देता है।

(iv) मानसिक क्रूरता मानसिक स्थिति है। एक पति या पत्नी में गहरी पीड़ा, निराशा,

निराशा की भावना दूसरे के आचरण के कारण लंबे समय तक मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है।

(v) पति या पत्नी को यातना, असहज करने या दुखद जीवन देने के लिए अपमानजनक और अपमानजनक उपचार का एक निरंतर पाठ्यक्रम।

(vi) एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार जो वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। व्यवहार की शिकायत और परिणामस्वरूप होने वाला खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और भारी होना चाहिए।

(vii) निरंतर निंदनीय आचरण, उपेक्षा, उदासीनता या वैवाहिक दया के सामान्य मानक से पूर्ण विचलन से मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने या दुखद आनंद प्राप्त करने से भी मानसिक क्रूरता हो सकती है।

(viii) आचरण ईर्ष्या, स्वार्थ, स्वामित्व से कहीं अधिक होना चाहिए, जो असंतोष का कारण बनता है और भावनात्मक परेशानी मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने का आधार नहीं हो सकता।

(ix) विवाहित जीवन की मात्र तुच्छ परेशानी, झगड़ा, सामान्य नोक झोंक जो मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए दिन-प्रतिदिन की जिंदगी में होता है पर्याप्त नहीं होगा।

(x) वैवाहिक जीवन की समग्र समीक्षा की जानी चाहिए और वर्षों की अवधि में कुछ अलग-थलग उदाहरण क्रूरता के बराबर नहीं होंगे। दुर्व्यवहार काफी लंबी अवधि तक लगातार रहना चाहिए, जहां रिश्ता इस हद तक बिगड़ गया है कि किसी पति या पत्नी के कृत्यों और व्यवहार के कारण, आहत पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ रहना बेहद मुश्किल लगता है, मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xi) यदि कोई पति बिना चिकित्सा कारणों के और अपनी पत्नी की सहमति या ज्ञान के स्वयं को नसबंदी के ऑपरेशन के लिए प्रस्तुत करता है और इसी तरह यदि पत्नी चिकित्सा कारणों के बिना या अपने पति की सहमति या ज्ञान के बिना वासेक्टोमी या गर्भपात करती है, तो पत्नी का ऐसे कार्य मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

(xii) किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के बिना काफी अवधि तक संभोग करने से इनकार करने का एकतरफा निर्णय मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी का एकतरफा निर्णय, विवाह से बच्चा नहीं होने का निर्णय क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xiv) जहां निरंतर अलगाव की लंबी अवधि हुई है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन मरम्मत से परे है। शादी एक कल्पना बन जाती है, हालांकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कानून द्वारा समर्थित है। उस बाँध को तोड़ने से इनकार करके, ऐसे मामलों में कानून विवाह की पवित्रता की सेवा नहीं करता है; इसके विपरीत,इससे पक्षों की भावनाओं और भावनाओं का कम ध्यान दिखाया जाता है। ऐसी स्थिति में मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है। “

24. विश्वनाथ अग्रवाल (ऊपर) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले को सुनाया जहां तलाक क्रूरता के आधार पर मांगा गया। समर घोष (उपरोक्त) के मामले में निर्णय सहित पूर्व निर्णय पर निर्भर करते हुए, यह इस प्रकार पाया गया:

"क्रूरता" अभिव्यक्ति का मानव आचरण या मानव आचरण से एक अविभाज्य संबंध है. यह हमेशा सामाजिक वर्ग या माहौल पर निर्भर करता है, जिसमें पार्टियां हैं, उनके जीवन के तरीके, रिश्ते, स्वभाव और भावनाएं जो उनकी सामाजिक स्थिति से निर्धारित हैं।

x x x

x x x

27. .... अलग से कहें तो मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि दोनों पक्षों से यथोचित रूप से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आहत पक्ष को यथोचित रूप से इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहना जारी रखने के लिए नहीं कहा जा सकता। इस निष्कर्ष पर पहुचते समय यह भी देखा गया कि इस संबंध में पार्टियों की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, जिस समाज में वे चलते हैं, पार्टियों की कभी भी एक साथ रहने की संभावना या अन्यथा अगर वे पहले से ही अलग रह रहे हैं तथा अन्य सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों का संबंध रखना चाहिए। किसी मामले में क्रूरता क्या है दूसरे मामले में क्रूरता के बराबर नहीं हो सकती और प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे निर्धारित करना होगा। इसके अलावा,आरोपों की उस संदर्भ में जांच की जानी चाहिए जिसमें वे लगाए जाते हैं। यह ध्यान दिया जाए कि उक्त मामले में, इस अदालत ने लिखित बयान में लगाए गए आरोपों और रिकॉर्ड में लाए गए सबूतों का व्यापक उद्धरण दिया और यह मानते हुए कहा कि उक्त आरोप और प्रतिवाद आरोप बचाव की साधारण याचिका के दायरे में नहीं थे और मानसिक क्रूरता के बराबर थे।

25. श्रीनिवास राव (ऊपर) के मामले में एक और निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने नवीन कोहली (ऊपर) के मामले में दिए गए पूर्व निर्णय के साथ ही समर घोष (ऊपर) के मामले में दिए गए कुछ और उदाहरण निम्नलिखित रूप से जोड़े:

16. इस प्रकार समर घोष में उल्लिखित मानसिक क्रूरता के उदाहरणों के लिए हम कुछ और जोड़ सकते हैं. याचिकाओं में पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ निराधार अभद्र मानहानि के आरोप लगाना, शिकायत दायर करना या नोटिस या समाचार जारी करना जो पति या पति के व्यापार की संभावना या नौकरी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं

और पति या पति के खिलाफ अदालत में बार-बार झूठी शिकायतें और मामले दायर करना, किसी मामले के तथ्यों में
दूसरे पति या पति के साथ मानसिक क्रूरता पैदा करने के बराबर होगा।

26. शारीरिक और मानसिक दोनों क्रूरता की अवधारणा के संबंध में उपर्युक्त अच्छी तरह से ठोस सिद्धांतों ने अब तक क्षेत्र को बनाए रखा है और व्यक्तिगत मामलों को अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर निपटने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। उपरोक्त निर्णय और उपरोक्त निर्णय की कटना में निर्धारित, दोहराया गया कानून को अग्रणी रखते हुए, हम वर्तमान मामले से निपटने के लिए यह पता लगाएंगे कि क्या अपीलकर्ता-पति क्रूरता को साबित करने में सफल रहा है ताकि उसे तलाक का अधिकार दिया जा सके।

27. शिकायत में किए गए विरोधाभासों का जिक्र करते हुए, इस आदेश के तीसरे पैराग्राफ में, हमने इस बारे में विस्तृत रूप से विचार किया है कि पति द्वारा दायर उदाहरण क्या हैं जो उसके अनुसार क्रूरता का गठन करते हैं। इस समय यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि क्रूरता का आरोप दो भागों में है। पहला वह है जो मूल रूप से शिकायत में मांगा गया था। दूसरा भाग पत्नी के पक्ष में पारित पत्नी अधिकारों की पुनर्वास के बाद की डिक्री है 6.5.2003. उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप के माध्यम से, अपीलकर्ता को याचिकाओं में संशोधन करने और याचिकाओं में अतिरिक्त सबूत देने और क्रूरता के अतिरिक्त आधार साबित करने की अनुमति दी गई। यह पत्नी अधिकारों की पुनर्वास के बाद की डिक्री का गठन करता है।

28. शिकायत में पहला आरोप पत्नी के असामान्य व्यवहार के संबंध में है, जैसे वह अपने पति के साथ रहेगी। याचिका के साथ-साथ वादी-अपीलकर्ता के साक्ष्य में यह कहा गया है कि जब वादी को बॉम्बे में नौकरी मिली और बॉम्बे के लिए आगे बढ़ी तो प्रतिवादी-पत्नी ने जोर देकर कहा कि वह अपने पति के साथ जाना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है जिसके कारण परिवार में कुछ मात्रा में विवाद और झगड़ा पैदा हो गया। पति और उसके गवाहों द्वारा जो सबूत दिया गया है, वह यह है कि हालांकि यह व्यक्त किया गया था कि उसके पति के लिए दोनों के लिए निवास का प्रबंधन करना मुश्किल होगा, प्रतिवादी-पत्नी अड़े हो गई और कहा कि वह रायपुर में वैवाहिक घर में नहीं रहेगी बल्कि केवल अपने पति के साथ बॉम्बे में रहेगी। जैसा कि दलील और सबूत दिखाते हैं, यह पक्षों के बीच विवाद का पहला मौका था। हालांकि, भले ही यह स्वीकार किया जाए कि प्रतिवादी-पत्नी इस बात
पर अड़े थी कि वह अपने पति के साथ बॉम्बे में रहेगी, हमें इसे पत्नी या उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा क्रूरता का उदाहरण मानना मुश्किल लगता है। कोई विशिष्ट दलील और न ही कोई सबूत यह दिखाने के लिए है कि इस विवाद को आगे बढ़ाते हुए, प्रतिवादी-पत्नी ने इस प्रकृति के आचरण में लिप्त किया या लिप्त किया जो क्रूरता का गठन करता है। "झागडे पर उतारू हो गई" जैसे अस्पष्ट शब्द बिना किसी विशिष्ट विवरण के साक्ष्य में बताए गए हैं इसलिए, पत्नी का ऐसा आचरण, कल्पना के किसी भी प्रकार से, और कुछ भी नहीं, उन निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित मानकों के अनुसार क्रूरता का गठन नहीं कर सकता जो यहां ऊपर उल्लिखित हैं-

क्रूरता का मामला स्थापित करने का अगला आरोप यह है कि बॉम्बे में, प्रतिवादी-पत्नी ने कुछ अवसर पर शर्मिंदगी पैदा की थी जब

अपीलकर्ता अपने कार्यालय से वापस आने के बाद घर बंद पाया और जब पत्नी बिना सूचना के कहीं और चली गई। पहला, अपीलकर्ता ने न तो अपनी याचिका में और न ही अपने साक्ष्य में ऐसी घटना की आवृत्ति के बारे में बताया है। पति और उसके गवाहों के नेतृत्व में सबूत बताते हैं कि पति अपनी पत्नी के साथ बॉम्बे में कुछ महीनों की बहुत कम अवधि तक रहता था। कितने मौकों पर घर बंद पाया गया था, यह घटना स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। यहां तक कि अगर इसे स्वीकार किया जाए, तो कुछ अवसर पर, जब अपीलकर्ता अपने कार्यालय से वापस आता है, तो घर बंद पाया जाता है, यह कानून के तहत समझा गया क्रूरता के बराबर नहीं होगा। यदि ऐसा क्रूरता का मामला माना जाता है, तो शायद हर मामले में क्रूरता के आधार पर तलाक के आदेश का आधार उत्पन्न होता।

30. इसकी भी याचिका की गई है और सबूत दिए गए हैं कि जब अपीलकर्ता हैदराबाद और पुणे में तैनात था, तो प्रतिवादी-पत्नी झगड़ा करते थे। शिकायत के पैरा-3 में यह दावा किया गया है कि जब अपीलकर्ता हैदराबाद और पुणे में तैनात था, तो पत्नी के रिश्तेदार आते थे और यह आरोप लगाते थे कि उसके घर में बिस्तर भी नहीं है और जिसके कारण प्रतिवादी झगड़ा करता था। इस संबंध में प्रतिवादी-पत्नी ने अपनी याचिका में अपने लिखित बयान
के पैरा-5 में कहा है कि अधिकांश समय अपीलकर्ता दौरे पर रहता था और पत्नी को दैनिक आवश्यकताओं का प्रबंधन करना पड़ता था, जिसका विवरण उसने अपने साक्ष्य में भी दिया है। उत्तरदाता-पत्नी को एक शिशु बच्चे की भी देखभाल करनी थी और इसके लिए, जैसा कि साक्ष्य में दलील दी गई और निष्कासित किया गया, उसे पड़ोसियों की भी मदद लेनी थी। उसने विशेष रूप से याचिका दी है और यह खारिज कर दिया है कि जब उसका बच्चा फर्श पर सो रहा था, तो एक जहरीले कीट ने बच्चे को काट दिया था और उसके बाद, जब प्रतिवादी-पत्नी ने बिस्तर खरीदने की मांग की, तो अपीलकर्ता ने दुर्व्यवहार किया और मारपीट भी की। इस क्रूर व्यवहार को पत्नी ने उसके रिश्तेदारों को सूचित किया, जो वहां आए थे और पति को सही व्यवहार करने की सलाह दी गई। इस संबंध में सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि उसके गवाहों ने भी सबूत दिए हैं। इस संबंध में पत्नी के इस सबूत से इनकार नहीं किया गया कि घर में कोई बिस्तर नहीं था और शिशु को एक जहरीले कीट ने काट दिया था। इसलिए, इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता का यह आरोप कि प्रतिवादी-पत्नी द्वारा उसे परेशान किया गया था क्योंकि घर में बिस्तर नहीं था, हमारे विचार में क्रूरता का मामला नहीं होगा।

31. अपीलकर्ता-पति ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि अपीलकर्ता उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद देने पर पत्नी अपीलकर्ता के साथ झगड़ा करती थी और वह आत्महत्या की धमकी भी देती थी। यह आरोप, हालांकि शिकायत में किया गया है,अस्पष्ट है। अपीलकर्ता की कुल आय क्या थी और उसकी आय का किस हिस्सा उसने अपनी मां या उसके भाई को भेजा था, न तो शिकायत में या साक्ष्य में कहीं भी नहीं बताया गया है। उनके साक्ष्य में यह भी नहीं बताया गया है कि उन्होंने अपनी मां और भाई को आर्थिक सहायता किस अवधि में दी थी। इस आधार

पर किसी तरह की विवाद का कोई विशेष उदाहरण नहीं बताया गया है। यह अस्पष्ट रूप से कहा गया है कि पत्नी धमकी देती थी आत्महत्या करना। इस संबंध में शिकायत के पैरा-7 में व्यक्त किया गया है जिसे विशेष रूप से प्रतिवादी-पत्नी ने अपने लिखित बयान में खारिज कर दिया है। इसके अलावा, लिखित बयान के पैरा-5 में यह दावा की गई है कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी को घरेलू मामलों को बनाए रखने, शिशु बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त धन नहीं दे रहा था और वह अधिकांश स्टेशन से बाहर रह रहा था।

32. पैरा-2 में निहित आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत हलफनामे पर उपलब्ध साक्ष्य, शिकायत के आरोप का केवल शब्दिक प्रजनन है और कोई विशिष्ट घटना की सूचना नहीं दी गई है।

उनके भाई संजय (AW2) ने इस संबंध में स्पष्ट सबूत नहीं दिए हैं। उन्होंने एक सामान्य बयान दिया है कि प्रतिवादी भोजन तैयार नहीं कर रही थी और हर मुद्दे पर वह परिवार की शांति को बाधित करती थी और आत्महत्या की धमकी देती थी। इसलिए, इस पहलू पर अपीलकर्ता (AW1) के सबूत उसके भाई संजय (AW2) के सबूतों से समर्थित नहीं हैं क्योंकि दोनों ने आत्महत्या की धमकी देने के अवसर के बारे में अलग-अलग तरीके से कहा है।

33. अपीलकर्ता की मां श्रीमती सावित्री गुप्ता (AW4) ने प्रतिवादी के ऐसे किसी भी आचरण के बारे में कुछ नहीं बताया है, जिसमें वह आत्महत्या की धमकी देती थी। यह भी ध्यान देने के लिए प्रासंगिक है कि अपीलकर्ता का आरोप यह है कि प्रतिवादी-पत्नी अपने भाई और मां के साथ रहते समय घरेलू मामलों में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही थी, लगातार झगड़े में आ रही थी, परिवार में शांति को बाधित कर रही थी, यह जोर देकर कि वह अपीलकर्ता के साथ रहेगी जहां भी वह तैनात है और रायपुर में सास और भाई के साथ नहीं, अपीलकर्ता की मां ने यह नहीं बताया है। सावित्री (AW4) जो अपीलकर्ता-पति के इस तरह के आरोप का समर्थन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में से एक थे। यहां तक कि संजय की पत्नी सुलेखा गुप्ता (AW5) ने आंतरिक पारिवारिक विवाद, लगातार झगड़े, कदाचार के बारे में कोई विशेष सबूत नहीं दिया है जैसा कि अपीलकर्ता ने अपनी याचिकाओं और सबूतों में आरोप लगाया था।

34. इस आरोप का समर्थन करने के लिए कि प्रतिवादी-पत्नी मां और भाई के साथ रायपुर के घर में रहने के लिए तैयार नहीं थी और वह झगड़ा कर रही थी, अपीलकर्ता ने नौकरानी उत्तरा की भी जांच की है। उनके सबूतों के अनुसार, प्रतिवादी और उसके पति और सास के बीच झगड़ा होता था, लेकिन सास ने इस बयान का समर्थन नहीं किया। इस गवाह के अनुसार, प्रतिवादी अक्सर यह कहती थी कि वह अपने माता-पिता के घर जाएगी और यह झगड़ा का कारण होता था। उसके अनुसार, उसे खाना पकाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और सास के साथ झगड़ा करती थी। हालांकि, इस सबूत को सास और बहन के सबूत से समर्थित नहीं किया गया है। इसके अलावा, इस गवाह के अनुसार, जब अपीलकर्ता अपनी नौकरी के संबंध में स्टेशन से बाहर चला गया था, तो झगड़ा होने के बाद प्रतिवादी अपने माता-पिता के घर चली गई थी, लेकिन अपीलकर्ता के खुद सबूतों के अनुसार, प्रतिवादी पत्नी आई थी उनके साथ बॉम्बे, पुना

और हैदराबाद में। हालांकि, यह नौकरानी अपने क्रॉस-परीक्षा में कहती है कि उसे नहीं पता कि अपीलकर्ता वापस आ गया है या अभी भी उसी नौकरी में काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यह महिला एक गढ़ी गवाह है क्योंकि वह परिवार के वर्तमान मामलों को भी नहीं जानती है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि झगड़ा का कारण क्या था। फिर से अपनी क्रॉस-परीक्षा में वह कहती है कि जब उसका पति अपनी नौकरी के संबंध में गया था, तो प्रतिवादी भी उसके साथ था। इस प्रकार, उसके सारे सबूत कि अपीलकर्ता नौकरी के संबंध में इस अवधि के दौरान स्टेशन से बाहर रह गया, प्रतिवादी-पत्नी, जो अपने वैवाहिक घर में रहती थी, झगड़े करने के लिए प्रयुक्त थी, स्वीकार योग्य नहीं है।

35. प्रतिवादी-पत्नी के लगातार झगड़े करने या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घरेलू मामलों में रुचि नहीं लेने या कुप्रेरक होने के संबंध में यह दलील और सबूत किसी विश्वसनीय सबूत से साबित नहीं किया गया है। अपीलकर्ता के गवाहों सहित अपीलकर्ता के साक्ष्य इस संबंध में विरोधाभासी हैं।

36. अपीलकर्ता ने तलाक के आदेश का दावा करने के लिए उस घटना पर बहुत अधिक निर्भर किया है जो उस समय हुई थी जब प्रतिवादी-पत्नी ने पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश की ताकत पर विवाह के घर में प्रवेश करने का प्रयास किया। यह आधार अतिरिक्त दलील और अग्रणी अतिरिक्त सबूतों के माध्यम से उठाया गया है। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि पत्नी के पक्ष में दाम्पत्य के अधिकारों की पुनर्वास का एक आदेश पारित किया गया था 6.5.2003 जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दी गई। धारा 125 के तहत रखरखाव अनुदान के लिए एक आवेदन किया गया था जिसे प्रतिवादी ने खुद और उसकी बेटी के लिए रखरखाव की मांग करते हुए भी दायर किया था, जिसमें कार्यवाही में 13.6.2005 को एक आदेश पारित किया गया था जिसके तहत,बेटी के पक्ष में प्रति माह 2,000 रुपये दिया गया, हालांकि यह माना गया कि प्रतिवादी-पत्नी अपना भरण पोषण रखने में सक्षम थी और उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष रिविजन हेतु याचिका की गई थी। आगे याचिका दी गई है कि अपील के लंबित होने के दौरान प्रतिवादी-पत्नी को रायपुर के आजाद चौक थाने में पति के खिलाफ झूठा आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसके कारण वह 23-24 अक्टूबर 2010 को जेल में रह गया था। अपने साक्ष्य में उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि 22.10.2010 को प्रतिवादी-पत्नी जबरन उस भाग में वैवाहिक घर में प्रवेश कर गई जहां उनका भाई बर्तन की दुकान चला रहा था। आरोप है कि जिन लोगों ने प्रतिवादी के साथ अपीलकर्ता को हिंसक तरीके से पकड़ लिया, गाली दी, धमकी दी कि अगर उन्होंने प्रतिवादी को वैवाहिक घर में निवास स्थान नहीं दिया तो उसे अपहरण कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई थी, पुलिस ने कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया, इसलिए अपीलकर्ता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जो अभी भी लंबित है। इस पहलू पर जब उनसे पूछताछ की गई तो वह स्वीकार करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दुकान में धारा 151 के तहत कार्रवाई के लिए आई थी। यह संस्वीकृति बताती है कि धारा 151 के तहत कार्यवाही शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा लेने के लिए उनके खिलाफ आकर्षित किया गया। वह आगे धारा 151 सीपीसी के तहत कार्यवाही को स्वीकार करता है। प्रतिवादी-

पत्नी ने न तो पेश हुए बंधपत्र और न ही जमानत देने पर कोई आपत्ति उठाई और बाद में, अपनी मां द्वारा पेश की गई सुरक्षा पर, उसे रिहा कर दिया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने धारा 151 सी०पी०सी० के तहत आदेशों और कार्यवाही की वैधता को चुनौती नहीं दी थी।

37. अपीलकर्ता के अन्य गवाह संजय गुप्ता (AW2) ने कहा है कि पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश की ताकत पर प्रतिवादी जबरन वैवाहिक घर में प्रवेश कर गया और जैसे ही वह पहुंची, उसने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। अपीलकर्ता के साथ-साथ इस गवाह के अनुसार, प्रतिवादी अदालत के आदेशिका वाहक के साथ आया था। हालांकि उन्होंने एस०एच०ओ० से आपराधिक मामला दर्ज करने का अनुरोध किया लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं किया गया इसलिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। इस गवाह ने अपनी पूछताछ में स्वीकार किया कि जिस दुकान में बर्तन रखा जाता है वह निवास का स्थान भी है और भाइयों के बीच कोई विभाजन नहीं है। उन्होंने अपनी पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उनके भाई यानी अपीलकर्ता को पुलिस ने आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब प्रतिवादी के निवेदन पर किया गया था, लेकिन अदालत के समक्ष कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है कि प्रतिवादी ने या तो अदालत के समक्ष या पुलिस के समक्ष उसके पति, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप लगाने के लिए कोई लिखित शिकायत दर्ज की थी। संजय (AW2) ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिवादी जमानत का विरोध करने के लिए एसडीएम के सामने कभी पेश नहीं हुआ।

38. सास श्रीमती सावित्री गुप्ता (AW4) ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी-पत्नी कोर्ट प्रोसेस सर्वर और अन्य लोगों के साथ दुकान में पहुंची और साथ में हमला भी किया।

39. किसी स्वतंत्र गवाह ने अपीलकर्ता और उसके गवाहों के मामले का समर्थन नहीं किया। अपीलकर्ता या उसके परिवार के किसी सदस्य के चोट के कोई सबूत नहीं है। हालांकि, अपीलकर्ता और उसके अन्य गवाहों ने सबूत में व्यक्त किया कि तस्वीरें ली गई थीं और घटना को वीडियो में भी बनाया गया था, ऐसे कोई विशेष सबूत नहीं मिले हैं। किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिवादी-पत्नी के साथ होने और अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को विवाहित घर में निवास स्थान आवंटित करने की धमकी देने का आरोप किसी आपराधिक कार्यवाही में साबित नहीं हुआ है। अपीलकर्ता के सबूत बताते हैं कि पुलिस ने ऐसे किसी आरोप पर कोई दानदार दर्ज नहीं किया बल्कि अपीलकर्ता है जिसके खिलाफ धारा 151 सीपीसी के तहत कार्यवाही की गई थी। एसडीएम द्वारा शांति का उल्लंघन करते हुए पाया गया और बाद में उन्हें बांड और सुरक्षा देने पर रिहा कर दिया गया। सबूत यह भी बताते हैं कि प्रतिवादी-पत्नी अदालत के प्रक्रिया सर्वर के साथ निवास स्थान मांगने के लिए वैवाहिक घर आई थी। कोई आरोप नहीं है कि प्रतिवादी-पत्नी ने किसी पर हमला किया या कोई हिंसक कार्य किया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी साबित किया जा सकता है वह यह है कि प्रतिवादी-पत्नी यह दावा करते हुए कि वह पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश के आधार पर सांझा घर में रहने का अधिकार रखती है। यह किसी भी गलत कार्य के बजाय वैवाहिक घर में निवास के अधिकार का प्रयोग करता प्रतीत होता है ना कि पति या उसके परिवार के

किसी भी सदस्य को परेशान करना। कई आरोप लगाए गए हैं कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ प्रतिवादी के साथ रहने वालों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, मामले की सूचना मीडिया को दी गई थी, इस संबंध में पहले कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले अदालत ने ऐसे आरोपों का समर्थन करने के लिए कहा, जो अधिक अतिरंजित प्रतीत होता था।

40. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने फैसले और पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश के खिलाफ अपील में इस अदालत की विभिन्न आदेश पत्रियों का उल्लेख किया कि यद्यपि मामला लंबित था, स्थगन की मांग की गई और इस अवधि के दौरान प्रतिवादी-पत्नी द्वारा विवाहित घर में प्रवेश करने का प्रयास किया गया। वह आगे कहेंगे कि इस अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ भी कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की है, यह देखकर असंतोष व्यक्त किया कि अपील लंबित है और पक्षों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है, इसलिए प्रतिवादी-पत्नी की ओर से अपीलकर्ता के घर में जबरन प्रवेश करना उचित नहीं था। दूसरी अपील में की गई टिप्पणी के आधार पर, यह कड़ी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी-पत्नी की ओर से क्रूरता का कार्य साबित हो गया है। गहन विचार करने के बाद हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। यह हो सकता है कि जब इस अदालत में कार्यवाही लंबित थी, तो प्रतिवादी को विवाह के घर में प्रवेश करने के लिए जोर नहीं देना चाहिए था, लेकिन यह कि अपने आप में, किसी क्रूरता का कोई सबूत नहीं होने पर, क्रूरता के आधार पर तलाक का आदेश देने का आधार नहीं बनाया जाएगा। विवाहित घर में आश्रय मांगने में प्रतिवादी-पत्नी का कार्य पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश की ताकत पर था। भले ही प्रतिवादी-पत्नी की ओर से ऐसी जल्दबाजी और जल्दबाजी का कार्य निंदनीय हो, यह कहना कि यह अपने आप क्रूरता का गठन करेगा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

41. अपीलकर्ता के नेतृत्व में कथित क्रूरता के सबूतों की अध्ययन और गहन जांच करने और आचरण की गंभीरता के मानकों को लागू करने पर, जो किसी पक्ष को क्रूरता के आधार पर तलाक का आदेश प्राप्त करने का अधिकार देगा, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि प्रतिवादी का आचरण ऐसे था कि यह क्रूरता का गठन करता है ताकि अपीलकर्ता को तलाक का आदेश देने का अधिकार हो। उन निर्णयों में जो यहां उल्लिखित हैं- ऊपर यह माना गया है कि क्रूरता को पारिवारिक जीवन के साधारण आचरण से अलग करना होगा। यह निर्णय पीड़ित पति या पत्नी की संवेदनशीलता के आधार पर नहीं किया जा सकता और आचरण के पाठ्यक्रम के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए जो सामान्य तौर पर पति या पति के लिए दूसरे के साथ रहना खतरनाक होगा। इसके अतिरिक्त क्रूरता का गठन करने के लिए, शिकायत करने वाला आचरण गंभीर और भारी होना चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता पति या पत्नी को यथोचित रूप से दूसरे के साथ रहने की उम्मीद नहीं किया जा सकता। यह वैवाहिक जीवन के सामान्य नोक झोंक से अधिक गंभीर होना चाहिए। आचरण को क्रूरता कहा जा सके, इससे पहले कि उसे गंभीरता की एक निश्चित पिच को छूना चाहिए। मात्र तुच्छ परेशानी, पार्टियों के बीच झगड़े क्रूरता के बराबर नहीं हो सकते।

वर्तमान मामले में क्रूरता के किसी भी उदाहरण को साबित नहीं किया गया है। पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आदेश की ताकत पर अदालत के प्रक्रिया सर्वर के साथ

विवाह के घर में प्रवेश करने की घटना स्वयं क्रूरता का गठन नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-पत्नी ने पति या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किसी अदालत या मंच में कोई अन्य कार्यवाही नहीं की है या कोई शिकायत नहीं की है, सिवाय पति के अधिकारों की पुनर्वास के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करना है। उन्होंने न तो पुलिस थाने में पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अपने पर क्रूरता का आरोप लगाया है और न ही पति के खिलाफ कोई घोटाला आरोप लगाया है। अपने लिखित बयान में दलीलें और उसके सबूत यह साबित करते हैं कि उसके साथ किए गए सभी मतभेदों के बावजूद, जो अन्य कार्यवाही में साबित पाया गया है, वह वैवाहिक घर वापस आने को तैयार थी, स्पष्ट रूप से क्योंकि उसकी एक बेटी थी और उसने वैवाहिक घर वापस लौटने और अपनी बेटी के भविष्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उसे अपने पति के खिलाफ एक से अधिक बार शिकायत करने का अवसर मिला लेकिन उसने किसी मंच पर अपीलकर्ता या परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले की कभी रिपोर्ट नहीं की। हमने पहले ही विराम के पहलू पर विचार किया है और यह निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह प्रतिवादी-पत्नी नहीं बल्कि अपीलकर्ता है जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि निम्न अदालत के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण है कि अपीलकर्ता अपने आचरण, कृत्यों, चूक के द्वारा अपीलकर्ता के साथ प्रतिवादी-पत्नी द्वारा की गई क्रूरता को साबित करने में विफल रहा।

43. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अंत में इस न्यायालय को यह समझाने की कोशिश की कि मामले में, विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, भले ही क्रूरता का आधार, कड़ाई से बोलते हुए, निर्धारित नहीं किया गया हो, तलाक का आदेश दिया जा सकता है। उनके द्वारा उद्धृत निर्णयों का जिक्र करते हुए, जिनका हमने यहां भी उल्लेख किया है, उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामला है जहां अपीलकर्ता-पति और प्रतिवादी-पत्नी पिछले 30 वर्षों से अपीलकर्ता के अनुसार कम से कम 27 वर्षों से एक साथ नहीं रह रहे हैं, भले ही प्रतिवादी के सबूत स्वीकार किए जाते हैं। वह आगे बताएंगे कि इस अवधि के दौरान, दोनों पक्षों को मध्यस्थता की प्रक्रिया के कई दौर के अधीन किया गया था, लेकिन सभी विफल हो गए। बेटी भी बड़ी हो गई है और मां के साथ रहती है। पक्षों के बीच विवाह में कुछ भी नहीं बचा है और ढाई दशक से अधिक समय के बाद पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है, इसलिए केवल इस आधार पर एक डिक्री दी जा सकती है। हालांकि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा जिन सभी निर्णयों का हवाला दिया गया है, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि चूंकि दोनों पक्ष एक साथ नहीं रह रहे थे और बहुत लंबे समय तक मुकदमेबाजी में संलग्न थे, उन मामलों की अन्य विशिष्ट परिस्थितियों के साथ मिलकर, विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया पाया गया, जिससे तलाक का आदेश दिया गया, लेकिन यह भी पाया गया कि तलाक का ऐसी आधार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में कानूनी रूप से निर्धारित नहीं है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय में उनके राज्यों ने यह भी टिप्पणी की है कि विधि आयोग की सिफारिश के मद्देनजर, उचित विधायी इसे तलाक के आधार में शामिल करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए लेकिन अब तक हिंदू विवाह अधिनियम में इस संबंध में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यद्यपि इस मामले में हम पाते हैं कि पक्षों के बीच विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है और पुनर्मिलन की कोई आशा या संभावना नहीं है, इस स्तर पर, 2012 की

एस०ए०एम० संख्या 138 का फैसला करते समय भी हम अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए उस आधार पर तलाक का आदेश देने में असमर्थ पाते हैं, खासकर जब, हमारे सामने उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय में न्यायिक रूप से विकसित नहीं हुआ है कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा तलाक का आदेश इस आधार पर दिया जा सकता है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है।

44. जहां तक 1998 के सिविल मुकदमा संख्या 5-क में पारित 6.5.2003 के निर्णय और आदेश को चुनौती देने का संबंध है, जिसके द्वारा विशिष्ट निचली अदालत ने पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के आवेदन की अनुमति दी है, प्रतिवादी-पत्नी के आवेदन में विशिष्ट याचिकाएं दी गई हैं कि शिकायत के पैरा-5 में वर्ष 1989 में प्रतिवादी-पत्नी अपनी बहन की विवाह में भाग लेने के लिए बलोदा बाजार गई थी। यह दावा किया गया है कि निमंत्रण के बावजूद अपीलकर्ता पति ने शादी में शामिल नहीं किया और न ही अपनी पत्नी को वापस लाने का कोई प्रयास किया। यह भी याचिका दी गई है कि प्रतिवादी के पिता, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों ने कई अवसरों पर अपीलकर्ता से संपर्क किया और उससे अपनी पत्नी और बच्चे को वापस वैवाहिक घर ले जाने का अनुरोध किया और अंत में मध्यस्थता के परिणामस्वरूप उसके पति ने वैवाहिक रिश्ते फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की लेकिन केवल 8 दिनों के बाद ही उसे मार्च 1992 में वापस माता-पिता के घर भेजा गया और तब से प्रतिवादी पत्नी अपनी नाबालिग बेटी रोशनी के साथ बलोदा बाजार में अपने माता-पिता के घर में रह रही है। आगे की याचिकाएं यह हैं कि बार-बार किए गए प्रयासों के बावजूद, अपीलकर्ता-पति ने अपनी पत्नी और बेटी की देखभाल करने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही उनके रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था की और इस प्रकार वैवाहिक दायित्व का पालन करने में लापरवाही की। शिकायत के पैरा-6 में यह भी दलील दी गई है कि 8.4.1997 को वैवाहिक संबंध बहाल करने का फिर से अनुरोध किया गया था लेकिन वकील के माध्यम से नोटिस के बावजूद, अपीलकर्ता ने पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। अपीलकर्ता-पति के लिखित बयान में यह हैं कि पत्नी का पिता प्रतिवादी को अपनी दूसरी बेटी की शादी में भाग लेने के लिए ले जाने आया था और तब झगड़ा हुआ था तब उसने प्रतिवादी-पत्नी को अपना सारा सामान लेने और फिर वापस न आने का कहा था और इस तरह प्रतिवादी-पत्नी ने अपने विवाहित घर छोड़ दिया। पत्नी द्वारा पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के लिए अपने आवेदन में की गई याचिकाएं यह हैं कि मार्च 1992 में वह अपने पति के घर आई थी लेकिन फिर से, अनैतिकता से उसे बाहर कर दिया गया था, जिससे इनकार किया गया है कि पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास की कोई वसूली हुई थी। यह दावा की गई है कि प्रतिवादी के विवाहित घर छोड़ने के बहुत समय बाद पति के अधिकारों की पुनर्वास के लिए आवेदन पति को झूठे तरीके से फंसाने का प्रयास है।

45. याचिकाओं में दोनों पक्षों ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर जाने के पहले के विवाद और तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि की याचिका दी है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर क्रूरता के आरोप लगाए हैं।

46. जबकि पत्नी द्वारा पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास के लिए अपनी आवेदन में की

गई याचिकाओं में विशिष्ट याचिकाएं की गई हैं कि अपीलकर्ता पति ने वर्ष 1989 में अपनी बहन की विवाह में न तो भाग लिया और न ही अपनी पत्नी और बेटी को वापस वैवाहिक घर ले जाने का प्रयास किया और अतिरिक्त कि यद्यपि पत्नी मार्च 1992 में वैवाहिक घर आई थी, उसे फिर से बाहर निकाल दिया गया, ऐसी याचिकाओं को अस्वीकार करने के अलावा पति द्वारा अपने लिखित बयान में कोई विशिष्ट याचिका नहीं दी गई है कि वह पत्नी और बेटी को अपने साथ रखने के लिए तैयार है या उसने उन्हें वापस लाने का प्रयास किया है या यहां तक कि पत्नी से विवाह के घर वापस आने का कोई मौखिक अनुरोध किया है। कोई विशेष दलील नहीं है कि पति और पत्नी के बीच विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान लाने के लिए उनकी ओर से कोई प्रयास किया गया है। इसलिए, जबकि पत्नी ने विशेष रूप से वैवाहिक जीवन बहाल करने के प्रयासों के बारे में याचिका दी है, पति की ओर से कोई याचिका नहीं दी गई है कि उसने प्रतिवादी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन बहाल करने का कोई प्रयास किया है।

47. पत्नी, जिन्होंने पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास की कार्यवाही में खुद का साक्ष्य कराया है, ने पैरा-23 में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि निमंत्रण के बाद उसे वर्ष 1989 में अपनी बहन की शादी में भाग लेने आना पड़ा, उसके पिता और अन्य रिश्तेदार उसे माता-पिता के घर ले जाने आए और उसे बलोदा बाजार लाया गया लेकिन बार-बार अनुरोधों के बावजूद पति शादी में भाग लेने नहीं आया और वह बलोदा बाजार में रहना जारी रखा। इसके अलावा पैरा-24 में उसने यह भी व्यक्त किया है कि हालांकि, उसके पिता ने कई मौकों पर पति से अपनी पत्नी को वापस लेने का अनुरोध किया था लेकिन अपीलकर्ता पति ने कोई कदम नहीं उठाया और अंत में वह अपने चाचा विजय के साथ अपीलकर्ता के घर गई और वहां 8-10 दिन तक रह गयी लेकिन अंत में उसे अपनी इच्छा के खिलाफ वर्ष 1992 में अपनी बेटी के साथ अपने माता-पिता के घर वापस भेज दिया गया। उसके बाद, उसे हटाया गया, उसके पति ने उसे वापस लेने नहीं आए और न ही उसके रखरखाव की कोई व्यवस्था की। उन्होंने यह भी कहा है कि मार्च 1992 के बाद भी उनकी बेटी और अन्य रिश्तेदारों ने कई प्रयास किए लेकिन अपीलकर्ता ने कभी स्वीकार नहीं किया और अंत में 8 अप्रैल 1997 को पति को पत्नी और बेटी को वापस लेने का कानूनी नोटिस दिया गया। उसे विस्तृत जांच कराई गई है। क्रॉस-परीक्षा में उसे दिया गया सुझाव कि वह 1989 में अपने माता-पिता के घर आने के बाद वह कभी वापस नहीं गई, को खारिज कर दिया गया है। उसने कहा है कि उसके पति ने उसे बलोदा बाजार में छोड़ दिया था और उसके पिता और कई अन्य लोगों के माध्यम से समझौता कराने के कई प्रयास किए गए थे। उन्होंने विशेष रूप से विवाद के निपटारे के लिए रविसोनी और गिरीश के प्रयासों को खारिज कर दिया है, जो रिश्तेदार हैं।

48. प्रतिवादी-पत्नी के नेतृत्व में उपरोक्त सबूत रवी (AW2), गिरीश (AW3) और उसके पिता भागवत सरफ (AW4) के सबूतों से समर्थित हैं। उनमें से प्रत्येक ने यह कहा कि किरण बाला 1989 में शादी में भाग लेने आने के बाद, उसके पति शादी में शामिल होने नहीं आया और न ही अपनी पत्नी और बेटी को वापस ले लिया, हालांकि कई प्रयास किए गए। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने खुद को एन०ए०डब्ल्यू-1 और उनकी मां सावित्री गुप्ता को एन०ए०डब्ल्यू-2 बताया। अपीलकर्ता ने अपने साक्ष्य में अस्वीकार

कर दिया है कि उनकी पत्नी फरवरी 1989 में बलोदा बाजार जाने के बाद वापस नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि वैवाहिक घर छोड़ने के समय उसने कहा कि वह फिर वापस नहीं आएगी। हालांकि, अपने सबूत में, उन्होंने कहीं नहीं बताया है कि क्या उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को वापसी के घर लाने का कोई प्रयास किया था। उन्होंने केवल आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसे क्रूरता का शिकार किया था और यह भी खारिज किया है कि उसकी मां और भाई के बीच प्रतिवादी-पत्नी के साथ झगड़ा होता था। यह भी स्वीकार किया जाता है कि फरवरी 1989 में उसके पिता और अन्य रिश्तेदार उसे लेने आए थे लेकिन उसके बाद उसने अपनी पत्नी को वापस वैवाहिक घर लाने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 8.7.1992 को पत्नी के पिता ने उन्हें पत्नी को वापस वैवाहिक घर ले जाने का नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पत्नी की जो सामान उनके द्वारा भेजा गया था, उसे उसके पिता बागवत प्रसाद स्वीकार नहीं कर रहे थे। अंत में, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि उन्हें पत्नी के अधिकारों की पुनर्वास पर गंभीर आपत्ति है। अपीलकर्ता पति की मां सावित्री गुप्ता (एन०ए०डब्ल्यू- 2) ने कहा है कि उनकी बहू 1988 से बलोडा बाजार में रह रही है और उसने घोषणा की है कि वह वैवाहिक घर में रहने को तैयार नहीं है। इस गवाह का सबूत विजय (एन०ए०डब्ल्यू- 1) द्वारा जो कहा गया है, उसके विरोधाभासी है कि पत्नी फरवरी 1989 में विवाह के घर से निकल गई। पैरा-3 में उसने स्वीकार किया है कि उसकी बहू/प्रतिवादी-पत्नी को वैवाहिक घर वापस लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

High Court of Chhattisgarh

49. रिकॉर्ड में सबूतों की जांच के बाद विद्वान निचली अदालत ने, जैसा कि ऊपर विचार किया गया, एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि प्रतिवादी-पत्नी का सबूत यह है कि उसे अपने पति द्वारा छोड़ दिया गया था और पति द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था, हालांकि, वह सामान्य वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने के लिए सभी प्रयास करते रहे, साबित हो गया है। सबूतों पर विचार करने पर हम यह भी मानते हैं कि प्रतिवादी-पत्नी ने न केवल विशेष रूप से याचिका दी है बल्कि यह भी स्पष्ट सबूत दिए हैं कि फरवरी 1989 में अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए माता-पिता के घर जाने के बाद विवाह के घर में झगड़ा की पृष्ठभूमि थी और अपीलकर्ता-पति शादी में भाग लेने नहीं आया और उसके बाद वह अपनी पत्नी और बेटी को वापस विवाह के घर ले जाने के लिए कभी भी बलोदा बाजार नहीं आया। इतना ही नहीं, पत्नी के पक्ष में विशिष्ट सबूत प्रस्तुत किये गये कि विभिन्न कार्यवाही में मध्यस्थता के माध्यम से पुनर्मिलन लाने के लिए कई प्रयास करते हैं परन्तु, अपीलकर्ता पति ने अधिकारों की पुनर्वास के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वास्तव में, उनके सबूत के अनुसार, अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह वैवाहिक संबंध फिर से शुरू करने के लिए तैयार नहीं है।

50. अपीलकर्ता-पति द्वारा क्रूरता और तलाक के आधार पर तलाक के आदेश की मांग करने वाली जुड़े हुए अपील (2012 की परिवार 138) में, रिकॉर्ड में सबूतों की सराहना के बाद, हमने यह स्पष्ट निष्कर्ष भी दर्ज किया है कि अपीलकर्ता-पति क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा है और यह कि पत्नी नहीं बल्कि अपीलकर्ता-पति है जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है।

51. उपरोक्त के मद्देनजर हमें प्रतिवादी-पत्नी के पक्ष में और अपीलकर्ता-पति के विरुद्ध दिए गए पति-पत्नी अधिकारों की पुनर्वास के विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता।

52. अपीलकर्ता-पति द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। तदनुसार अलग अपील डिक्री बनाई जाए। व्यय आसान की गई है।

एसडी/-
(मनिंन्द्र मोहन श्रीवास्तव**)**
न्यायाधीश

एसडी/-
(विमला सिंह कपूर**)**
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur